Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

# कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-04 16-28 फरवरी, 2023 (पाक्षिक) ₹20

भाजपा का 'संकल्प पत्र' : त्रिपुरा के विकास का रोडमैप

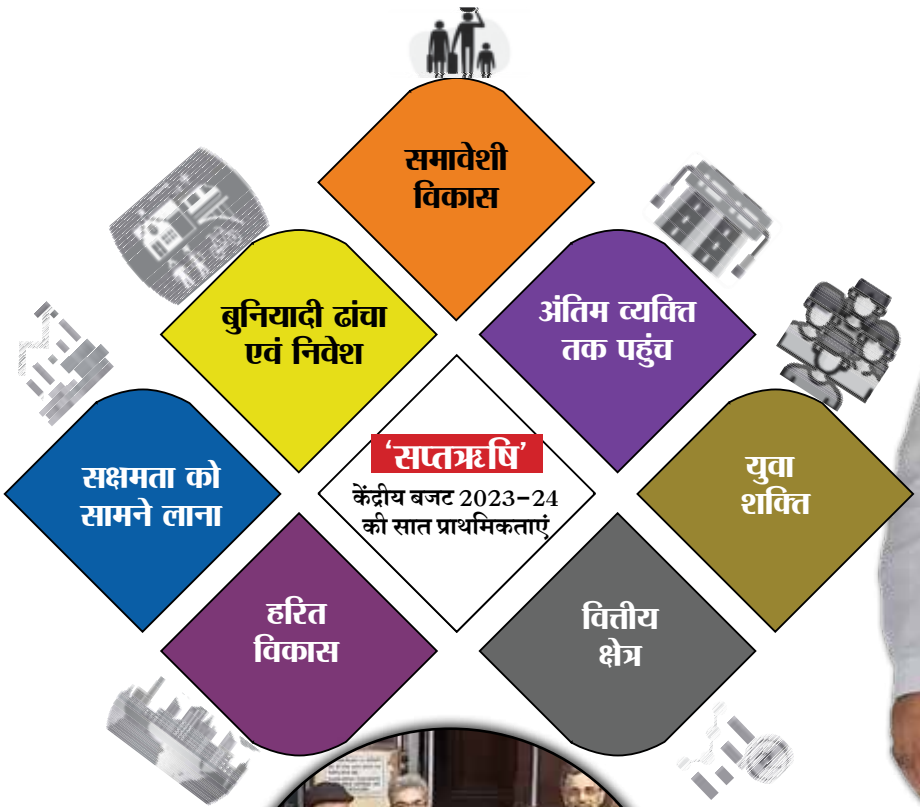

## बजट 2023-24

## विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों के लिए एक मजबूत नींव

कुमारघाट (त्रिपुरा) में 03 फरवरी, 2023 को विशाल 'विजय संकल्प रैली' को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 27 जनवरी, 2023 को केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

भाजपा मुख्यालय में 30 जनवरी, 2023 को 'भाजपा को जानो' पहल के तहत तंजानिया की सत्ताधारी पार्टी चामा चा मापिन्दुज़ी (सीसीएम) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

जसीडीह (देवघर, झारखंड) में 04 फरवरी, 2023 को विशाल 'विजय संकल्प रैली' को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

बेलगावी (कर्नाटक) में 28 जनवरी, 2023 को एक जनसभा में जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

बरजाला (त्रिपुरा) में 07 फरवरी, 2023 को विशाल 'विजय संकल्प रैली' को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

# कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

**संपादक**
प्रभात झा

**कार्यकारी संपादक**
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

**सह संपादक**
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

**कला संपादक**
विकास सैनी
भोला राय

**डिजिटल मीडिया**
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

**सदस्यता एवं वितरण**
सतीश कुमार

**इ-मेल**
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
**वेबसाइट:** www.kamalsandesh.org


# विषय-सूची

06 **'अमृत काल' के विजन को प्रस्तुत करता है केंद्रीय बजट 2023-24**

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। केन्द्रीय बजट 'अमृत काल' के लिए विजन प्रस्तुत करता है तथा यह एक सशक्त और समावेशी...

16 **भाजपा का 'संकल्प पत्र' : त्रिपुरा के विकास का रोडमैप**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 फरवरी, 2023 को रबींद्र...

24 **राष्ट्रपति का संसद के समक्ष अभिभाषण**

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को कहा कि देश में अमृतकाल का 25 वर्ष का कालखंड, स्वतन्त्रता की स्वर्णिम...

26 **लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का जवाब**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब लोकसभा में दिया...

32 **भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न**

भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 29-30 जनवरी, 2023 को बेलगांव (कर्नाटक)...

## लेख

अमृतकाल में सहकारिता की अहम भूमिका / **अमित शाह** 24

## अन्य

'बजट आकांक्षी समाज, गरीबों, गांवों और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास करता है' 08

इस बजट से विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा: जगत प्रकाश नड्डा 09

केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य बातें 10

विकासोन्मुखी बजट के साथ किसानों, महिलाओं, वंचित वर्गों व मध्यम वर्ग को प्राथमिकता: राजनाथ सिंह 12

सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट: अमित शाह 13

त्रिपुरा अब आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा से मुक्त है: राजनाथ सिंह 17

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का विशाल विजय संकल्प जनसभा त्रिपुरा एवं झारखंड 18

सरकार की उपलब्धियां: आर्थिक समीक्षा 2022-23 19

'वंदे भारत ट्रेनें भारत की गति और पैमाने का प्रतिबिंब हैं' 27

प्रधानमंत्री ने 'परीक्षा पे चर्चा 2023' में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत 30

'मन की बात' 32

प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता: सर्वे 34



प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

# सोशल मीडिया से

### नरेन्द्र मोदी

जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो पूरा समाज सशक्त होता है और जब समाज सशक्त होता है तो पूरा देश सशक्त होता है। मुझे संतोष है कि माताओं, बहनों और बेटियों की सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। (08 फरवरी, 2023)

### जगत प्रकाश नड्डा

आज त्रिपुरा स्थित मां मंगलचंडी की पुण्यधरा अमरपुर की जनसभा में जन-जन का उत्साह बता रहा है कि प्रदेश में भाजपा पर लोगों का अटूट विश्वास है। अराजकता, कुशासन व पिछड़ेपन से मुक्त होकर प्रदेश अब भाजपा के जनसेवा के संकल्प के साथ प्रगति व समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। (03 फरवरी, 2023)

### अमित शाह

चाहें दीवारों पर पेंटिंग हो, दरी बिछाना हो या पार्टी के प्रचार के लिए घर-घर जाना, भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन के सभी छोटे-बड़े कामों को पूरे दिल से करता है और यही भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है। आज कर्नाटक में चलाये जा रहे 'विजय संकल्प अभियान' में पार्टी के प्रचार में भाग लिया। (28 जनवरी, 2023)

### राजनाथ सिंह

त्रिपुरा की राजनीति में भाजपा को 'जीरो' से 'सुपर हीरो' बनाने का काम आप लोगों ने किया है। माकपा ने लंबे समय तक त्रिपुरा में शासन किया, परन्तु इन लोगों ने प्रदेश की जनता का शोषण किया। अब त्रिपुरा राज्य को हीरा (HIRA) मिल गया है... (07 फरवरी, 2023)

### बी.एल. संतोष

सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100 प्रतिशत यांत्रिक डी-स्लजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। मैनहोल से मशीन होल मोड में बड़ा परिवर्तन। अतुल्य सामाजिक सुधार। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार। (1 फरवरी, 2023)

### डॉ. के. लक्ष्मण

भारतीय नौसेना ने रचा इतिहास, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान बनाकर तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। (8 फरवरी, 2023)

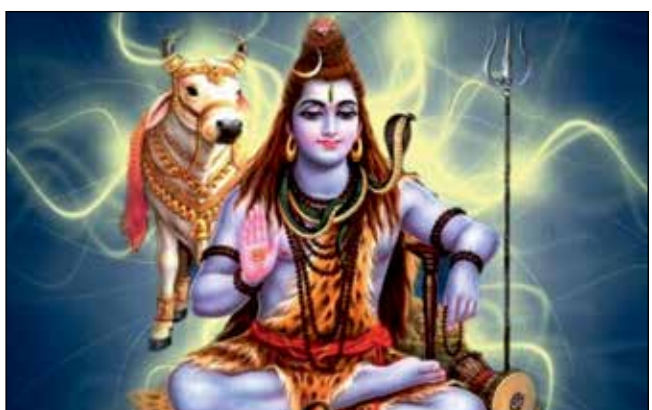

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
**महाशिवरात्रि** (18 फरवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

# समृद्ध भारत का समावेशी बजट

अमृतकाल के पहले बजट से आने वाले 25 वर्षों में एक विकसित एवं समृद्ध भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प परिलक्षित हो रहा है। एक ओर जहां केंद्रीय बजट 2023-24 ने एक गौरवशाली भविष्य की नींव रखी है, वहीं दूसरी ओर गरीब, वंचित, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं युवा के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ करने का लक्ष्य इसमें दिख रहा है। इस बजट की दृष्टि को सात प्राथमिकताओं को 'सप्तऋषि' के रूप में देखा जा सकता है, जो हर क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए विकास का 'अमृत' हर व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प से प्रेरित है। समावेशी विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर बल देते हुए अवसंरचना एवं निवेश को बढ़ावा, क्षमता विस्तार, हरित विकास पर जोर, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से यह बजट हर व्यक्ति के लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह बजट अर्थव्यवस्था में त्वरित विकास एवं अर्थव्यवस्था के मानदंडों में स्थिरता के माध्यम से रोजगार सृजन कर युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। बजट का लक्ष्य एक 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' के निर्माण का है जो प्रौद्योगिकी युक्त, ज्ञान केंद्रित तथा भविष्योन्मुखी लक्ष्यों से परिपूर्ण है।

**देश की अर्थव्यवस्था आज एक मजबूत स्थिति में है। विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से बजट 2023-24 लोगों की आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। एक ओर मध्यम वर्ग को आयकर में भारी राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कभी कांग्रेसनीत यूपीए के दौर में दहाई आंकड़े की मुद्रास्फीति, पॉलिसी पैरालिसिस, विकास दर में गिरावट की पर्याय बन चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था आज पूरे विश्व में एक चमकते सितारे के रूप में उभरी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप जहां आज विश्व भर में आर्थिक संकट गहराया हुआ है, भारत न केवल उन परिस्थितियों से उबरा है, बल्कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। आज प्रति व्यक्ति आय पिछले नौ वर्षों में दुगुनी हो चुकी है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें पायदान से उठकर आज पांचवें स्थान पर आ चुकी है। इतना ही नहीं, कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत में अत्यंत गरीबी की दर 1 प्रतिशत से भी कम हो चुकी है तथा पिछले डेढ़ दशक में 41.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। सामाजिक क्षेत्र में निवेश दुगुना होकर 21.3 लाख करोड़ रुपए हो चुका है तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से बिचैलियों को हटाते हुए 27 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांरित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक एवं प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जिसका प्रभाव आज कई क्षेत्रों में क्षमता-विकास एवं चमत्कारी परिणामों के रूप में देखा जा सकता है।

देश की अर्थव्यवस्था आज एक मजबूत स्थिति में है। विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से बजट 2023-24 लोगों की आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। एक ओर मध्यम वर्ग को आयकर में भारी राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। 157 नए नर्सिंग महाविद्यालय शुरू करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 79,000 करोड़ का प्रावधान, गोवर्धन योजना के अंतर्गत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट शुरू करने, 30 नए अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र प्रारंभ करने, रेलवे के लिए अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की स्थापना, सभी महानगर एवं शहर में सेप्टिक टैंक एवं सीवर का यंत्रों द्वारा सफाई, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, 2030 तक 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य, राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो अर्थव्यवस्था को भविष्योन्मुखी दृष्टि के साथ आगे ले जाएंगे। आज जब देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं मजबूत नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सर्वसमावेशी, भविष्योन्मुखी एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं अभिनंदन। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

# 'अमृत काल' के विजन को प्रस्तुत करता है केंद्रीय बजट 2023-24

## मध्यम वर्ग के लिए भारी राहत, 7 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। केन्द्रीय बजट 'अमृत काल' के लिए विजन प्रस्तुत करता है तथा यह एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में पूरी दुनिया ने यह भलीभांति स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक 'चमकता सितारा' है, क्योंकि कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर व्यापक सुस्ती दर्ज किए जाने के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। दरअसल, भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और मौजूदा समय में तरह-तरह की चुनौतियां रहने के बावजूद भारत उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है

### अमृत काल के लिए विजन– एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अमृत काल से जुड़े हमारे विजन में मजबूत सरकारी वित्तीय स्थिति के जरिए प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित करना शामिल है, जिसे हासिल करने के लिए 'सबका साथ सबका प्रयास' के जरिए जन-भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले बजट में डाली गई मजबूत नींव और भारत@100, जिसमें एक समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना की गई है, के लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के सहारे

**'अमृत काल' के विजन के आर्थिक एजेंडे की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं**

- नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक अवसरों को उपलब्ध कराना
- प्रगति और रोजगार सृजन के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराना
- वृहद आर्थिक सुस्थिरता को मजबूत बनाना

## 'सप्तऋषि'

'अमृत काल' के पहले बजट का निम्न सात प्राथमिकताओं द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, जो सप्तऋषि की तरह एक दूसरे का सम्पूरण करती हैं:

1. **समावेशी विकास**
2. **अंतिम व्यक्ति तक पहुंच**
3. **बुनियादी ढांचा एवं निवेश**
4. **सक्षमता को सामने लाना**
5. **हरित विकास**
6. **युवा शक्ति**
7. **वित्तीय क्षेत्र**

भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा, जहां आर्थिक विकास के फल सभी क्षेत्रों एवं समस्त नागरिकों विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि अनगिनत उपलब्धियों जैसेकि अनूठी विश्वस्तरीय सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना यथा आधार, को-विन और यूपीआई; अभूतपूर्व पैमाने एवं गति से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाए जाने; अग्रणी क्षेत्रों में अति सक्रिय भूमिका निभाने जैसेकि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल कर लेने, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बदौलत ही भारत की वैश्विक साख निरंतर दमदार होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, जिसके लिए सरकार ने 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की विशेष योजना 28 महीनों तक चलाई।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए सरकार 1 जनवरी, 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की योजना चला रही है, जो अगले एक साल तक जारी रहेगी। केन्द्र सरकार द्वारा ही कुल मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का समूचा खर्च वहन किया जाएगा।

श्रीमती सीतारमण ने इस ओर ध्यान दिलाया कि अनेक योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन और सभी लोगों को लक्षित लाभ देने की बदौलत समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ है। वित्त मंत्री ने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया, जैसेकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए, उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 102 करोड़ लोगों को कोविड टीके की 220 करोड़ खुराक दी गई, 47.8 करोड़ पीएम जन-धन बैंक खाते खोले गए, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया गया।

# बजट आकांक्षी समाज, गरीबों, गांवों और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास करता है : नरेन्द्र मोदी

**'अमृत काल' का यह पहला बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों के लिए एक मजबूत नींव रखता है**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक फरवरी को कहा कि भारत के 'अमृत काल' में पहले बजट ने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वंचितों को वरीयता देता है और आकांक्षी समाज, गरीबों, गांवों और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास करता है।

उन्होंने वित्त मंत्री और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने पारंपरिक कारीगरों जैसेकि बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार और कई अन्य शिल्प को जानने वाले लोगों को राष्ट्र निर्माता कहा।

उन्होंने कहा कि पहली बार देश इन लोगों की कड़ी मेहनत और सृजन के सम्मानस्वरूप कई योजनाएं लेकर आया है। उनके लिए प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संबंधी सहयोग की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।

## सशक्त होंगी महिलाएं

श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने शहरों से लेकर गांवों में रहने वाली और कामकाजी महिलाओं से लेकर गृहणियों तक के लिए जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना आदि जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो उन्हें सशक्त बनाएंगे और उनके कल्याण को सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह बजट सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। इस बजट में नई प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा भी की गई है। इससे खेती के साथ-साथ दूध एवं मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा और किसानों, पशुपालन में संलग्न लोगों तथा मछुआरों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे।

### ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स

यह बजट टिकाऊ भविष्य के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। इस बजट में प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था पर काफी जोर दिया गया है। आज का आकांक्षी भारत सड़क, रेल, मेट्रो, बंदरगाह और जलमार्ग जैसे हर क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना चाहता है। वर्ष 2014 की तुलना में बुनियादी ढांचे में निवेश 400 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है

प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान की सफलता को कृषि क्षेत्र में दोहराने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह बजट डिजिटल कृषि बुनियादी ढांचे की एक बड़ी योजना लेकर आया है।

उन्होंने बताया कि दुनिया अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मना रही है और कहा कि भारत में कई नामों से कई प्रकार के मोटे अनाज मिलते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब मोटे अनाज दुनिया भर के घरों में पहुंच रहे हैं, तो इनकी विशेष पहचान जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुपरफूड को 'श्री-अन्न' नाम से एक नई पहचान दी गई है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि देश के छोटे किसानों और आदिवासी किसानों को देश के नागरिकों के लिए स्वस्थ जीवन के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी मिलेगी।

उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि बुनियादी ढांचे पर दस लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश भारत के विकास को नई ऊर्जा और गति देगा। श्री मोदी ने बताया कि इन निवेशों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे बड़ी आबादी को आय के नए अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण गारंटी की व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने बताया कि अनुमानित कर की सीमा बढ़ाने से एमएसएमई को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

## मध्यम वर्ग को भारी राहत

प्रधानमंत्री ने 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की ताकत को रेखांकित किया। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कर की दरों में कमी के साथ-साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पारदर्शिता और तेजी पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा कि हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़े रहने वाली हमारी सरकार ने उन्हें करों में भारी राहत दी है। ■

# इस बजट से विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगाः जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'बजट 2023-24' को अमृत काल का पहला आम बजट बताते हुए कहा कि इससे विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री नड्डा ने एक फरवरी, 2023 को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक-कल्याणकारी और देश के विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

## बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताएं

श्री नड्डा ने कहा कि आम बजट 2023-24 का एजेंडा है— नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की 7 अर्थात् सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं— समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है।

## आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किये जाने का निर्णय श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। इस योजना के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है, जिससे पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। मैं श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किये जाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागतयोग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि मैं श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के निर्णय का भी स्वागत करता हूं। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

## 'हरित विकास' का लक्ष्य

श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2023-24 का आम बजट 'हरित विकास' के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो 2019-20 की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है।

## गरीबों के प्रति संवेदनशीलता

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर 79 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है।

## सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा

श्री नड्डा ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। ■

# केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य बातें

## प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में दोगुनी

- प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है।
- वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं।
- उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
- 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार।
- 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज।
- पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण।
- पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।
- लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।

## पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि

- केन्द्र का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 13.7 लाख करोड़ रुपये।
- रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
- अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और पूरक नीतिगत कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज रहित कर्ज को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा।
- हमारे शहरों को 'भविष्य के स्थायी शहरों' में बदलने के लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल है।
- अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया

अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित किया गया।

- शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- राज्यों के निमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किये जाने हैं, इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तवित पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा।
- राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषी घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।

## शिक्षा व कौशल विकास

- वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- केन्द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट

स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

- विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिनसे नये अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी।
- 'कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमता से भारत के लिए कार्य कराएं' के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे।
- भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।
- एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत कर कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने, एमएमएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा।
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।

## 20 लाख करोड़ रुपये तक कृषि ऋण

- कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्य शृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा।
- कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।
- सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया है।
- व्यापक विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया

है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- भारत को 'श्री अन्न' के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।
- आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।

## प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर

- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।
- सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के लिए केन्द्रीय मदद के रूप में 5300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500

# विकासोन्मुखी बजट के साथ किसानों, महिलाओं, वंचित वर्गों व मध्यम वर्ग को प्राथमिकता: राजनाथ सिंह

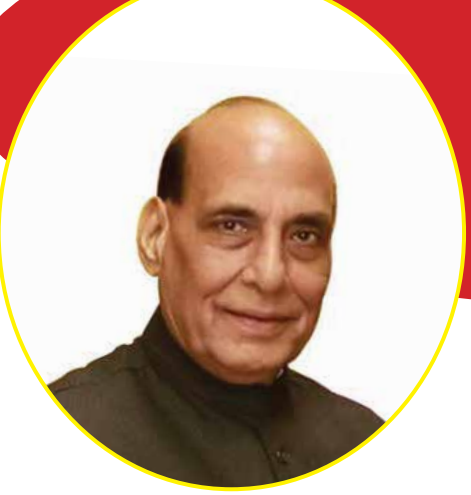

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकासोन्मुखी केंद्रीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं, हाशिये पर पड़े वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है।

सिलसिलेवार ट्वीट में श्री सिंह ने एक फरवरी को कहा कि ये बजट ऐसी विकास संबंधी और कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करेगा जिसमें छोटे व्यवसायों के मालिक, किसान और पेशेवर शामिल हैं।

रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्रीय बजट 2023-24 कुछ ही वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के साथ ही कृषि, आवास, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में अधिक खर्च से सभी के लिए नौकरियों के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे तथा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ाकर और कई अन्य कर संबंधित सुधारों से वेतनभोगी व्यक्तियों और सेवानिवृत्त लोगों सहित मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत मिलेगी। मैं लोगों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ■

---

नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।

## राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
- ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी।
- 'पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।
- मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल, मिश्टी की शुरुआत की जाएगी।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
- अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

## एमएसएमई को मजबूती

- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल, 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा, ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चेरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी।
- कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित

# सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट: अमित शाह

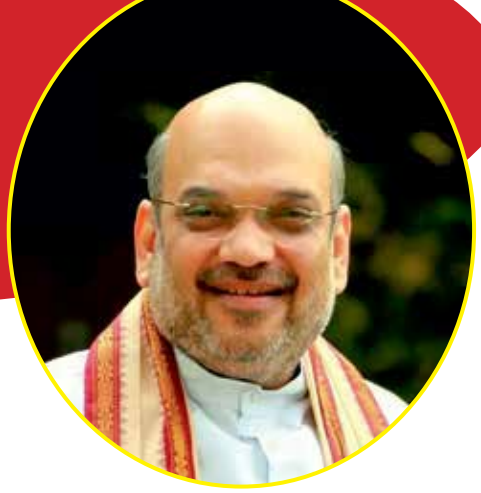

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी।

अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में श्री शाह ने एक फरवरी को कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट 2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9% रखने का लक्ष्य सराहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

श्री शाह ने यह भी कहा कि मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों को दी गई राहत का भी मै स्वागत करता हूं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री शाह ने कहा कि इस बजट में कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही, अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी और 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर (Bio Input resource centre) बनाए जाएंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही, देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

श्री शाह ने कहा कि इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। ■

---

करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा।

- प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए 'परिणाम-आधारित' वित्त पोषण।

## अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य

- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये।
- सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीनयुक्त बनाने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा।
- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
- राज्यों के उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा।
- सहयोगपरक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ओषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

## कारोबार में सुगमता

- कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया।
- सरकारी की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में 42 केन्द्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया।
- व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
- लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केन्द्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई-गोट कर्मयोगी का शुभारंभ।

## पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग

- स्थायी खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।
- न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू किया जाएगा।
- एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

## 7 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं

- नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
- नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
- नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
- गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
- नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।

## अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान कर दायरे से बाहर

- अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव। अग्निवीरों की कुल आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केन्द्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांरित किया है।

## बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया

- वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया।
- कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।
- सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।
- हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।
- मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए कुछ एक पूर्जों और कैमरा लैंसो जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम-आयान बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष लिए जारी रखना प्रस्तावित।
- टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

## कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को किया जाएगा विकसित

- चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।
- आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
- मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया।
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।
- पहले चरण में 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपीग्राफी संग्रहालय में 'भारत शेयर्ड रिपोजटरी ऑफ इनस्क्रिप्शंस' की स्थापना।

## स्टार्ट-अप को बढ़ावा

- स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक करने का प्रस्ताव।
- स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव।
- गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा।
- चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने का अवसर दिया गया है। इससे इन्हें लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की उम्मीद है।
- प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस) और प्राथमिक कॉपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव।
- सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी निकासी पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।

## संशोधित अनुमान 2022-23

- उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं।
- राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है, जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

## बजट अनुमान 2023-24

- बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
- निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- 2023-24 में राजकोषीय़ घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ■

# भाजपा का 'संकल्प पत्र' : त्रिपुरा के विकास का रोडमैप

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 फरवरी, 2023 को रबींद्र भवन, अगरतला में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के निमित्त भाजपा 'संकल्प पत्र' जारी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-गठबंधन की डबल इंजन वाली सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में राज्य में हुए विकास कार्यों को उल्लेखित करते हुए विश्वास व्यक्त किया और कहा कि अगले पांच वर्षों में हम त्रिपुरा को एक समृद्ध प्रदेश बनायेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का 'संकल्प पत्र' त्रिपुरा के विकास का रोडमैप है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लब देब, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य, नॉर्थ-ईस्ट के भाजपा कोऑर्डिनेटर डॉ. संबित पात्रा, को-कोऑर्डिनेटर श्री ऋतुराज सिन्हा, श्री महेश शर्मा एवं प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्री महेंद्र सिंह और संकल्प पत्र समिति के चेयरमैन श्री अशोक सिन्हा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और त्रिपुरा सरकार में मंत्री व विधायक उपस्थित थे।

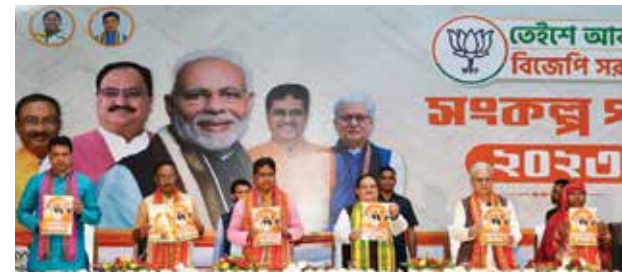


### प्रमुख संकल्प: 'उन्नत त्रिपुरा - श्रेष्ठ त्रिपुरा' संकल्प पत्र 2023

त्रिपुरा के लिए भाजपा के संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाओं को उद्धृत करते हुए श्री नड्डा ने कहा—

- **महिला सशक्तीकरण:** हम बालिका समृद्धि स्कीम लाएंगे। घर में लक्ष्मी आने पर वित्तीय रूप से गरीब हर परिवार को 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। उज्ज्वला के लाभार्थियों को हर साल दो गैस सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा।
- **शिक्षा:** महाराजा वीर बिक्रम माणिक्य यूनिवर्सिटी स्थापित की जायेगी। इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बेम्बू टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। त्रिपुरा टाइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा हर ब्लॉक में एक एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। युवाओं के लिए त्रिपुरा कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसमें लगभग दो लाख आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **आवास एवं भोजन:** 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण और शहरी के तहत सभी पंजीकृत लाभार्थियों को किफायती आवास उपलब्ध कराएंगे। सभी योग्य भूमिहीन नागरिकों को भूमि पट्टे का वितरण करेंगे। हर महीने सभी योग्य पी.डी.एस (PDS) लाभार्थियों को मुफ्त चावल और गेहूं का आवंटन एवं वर्ष में चार बार रियायती दर पर खाद्य तेल उपलब्ध कराएंगे।
- **त्रिपुरा जनजाति विकास योजना:** त्रिपुरा जनजाति विकास योजना के तहत आदिवासी भाइयों के परिवार को सालाना 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। समाजपतियों को मिलने वाले ऑनरेरी मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा।
- **कृषि एवं किसान कल्याण:** श्री नरेन्द्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। हमने यह निर्णय लिया है कि त्रिपुरा में आने वाली भाजपा सरकार अपने स्तर पर किसानों को हर साल 2,000 रुपये देगी। इस तरह त्रिपुरा के किसानों को हर साल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8,000 रुपये मिला करेंगे। साथ ही, भूमिहीन किसान विकास योजना के तहत भूमिहीन किसानों को सालाना 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी। मत्स्य सहायक योजना के तहत मछुआरों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- **स्वास्थ्य:** 'आयुष्मान भारत' के तहत कार्ड धारक को हर साल 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हमारी सरकार बनने पर त्रिपुरा में आयुष्मान कार्ड धारकों को अब 10 लाख रुपये तक का इलाज सालाना मुफ्त मिलेगा।
- **निवेश एवं उद्योग:** त्रिपुरा के विकास के लिए निवेश को आकर्षित करेंगे। अगले पांच साल में हम त्रिपुरा में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश लायेंगे।
- **गुड गवर्नेंस एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट:** गुड गवर्नेंस 2.0 के तहत हर घर सुशासन पहुंचाने के लिए मतलब अच्छे तरीके सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी घरों में नल का पानी पहुचाएंगे। अगले 5 वर्षों में राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ त्रिपुरा रोड मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को और विकसित करने के लिए त्रिपुरा उन्नत ग्राम कोष में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।
- **कला एवं पर्यटन:** झारखंड में देवघर और उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ के लिए रियायती ट्रेन यात्रा, आवास और भत्ता सहित एक विशेष पैकेज की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ योजना शुरू जिसमें अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन आदि के लिए ट्रेन यात्रा, आवास और भत्ता सब्सिडी देंगे। ■

# त्रिपुरा अब आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा से मुक्त है: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के दक्षिण जिले में स्थित एक सीमावर्ती गांव राजनगर में आठ फरवरी, 2023 को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 में भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के लोग अब उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा से मुक्त हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा भी उपस्थित रहे।

रक्षा मंत्री ने कहा, "बांग्लादेश की सीमा राजनगर के बहुत पास है। अब यहां बाड़ लगा दी गई है और इसलिए बांग्लादेशी यहां से अवैध रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस और माकपा सरकार के समय बाड़ नहीं लगाई गई थी और यह काम तब शुरू हुआ जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस और माकपा सरकार के दौरान उग्रवाद की गतिविधि अपने चरम पर थी। प्रदेश में किसी को नहीं पता था कि कौन हमला करेगा और कब करेगा, लेकिन त्रिपुरा में भाजपा के आने और सरकार बनने के बाद स्थिति में भारी बदलाव आया है। अतीत में लोगों ने अतिवाद, आतंकवाद और हिंसा के कारण बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वे इन सबसे मुक्त हैं।'

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव प्रचार- 2023

उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा ने 'चलो पलटाई' का नारा दिया था, अब हर कोई कहेगा 'चलो सुशासन को मजबूत बनाएं।'

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, "हमारा दल राष्ट्रीय स्तर का है, यह माकपा की तरह एक छोटे प्रदेश का दल नहीं है। पिछले 20 साल से मैं त्रिपुरा का दौरा कर रहा हूं और मैंने वहां का हाल देखा है। 2005 से 2018 तक यह माकपा की सरकार थी और उस दौरान त्रिपुरा को एक अविकसित प्रदेश के तौर पर जाना जाता था। 2018 के बाद ही असल विकास त्रिपुरा में हुआ। यह अब एक नया त्रिपुरा है।"

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें पांच साल और दीजिए, हम त्रिपुरा को देश का नंबर एक प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि भाजपा इस बार 2018 के चुनाव से ज्यादा सीटें जीतेगी।' ■

## डी. आर. थापा भाजपा सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किये गये

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने चार फरवरी, 2023 को श्री डी.आर थापा को भाजपा, सिक्किम प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी ने एक वक्तव्य में कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री एन. के. सुब्बा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया और विधायक श्री डी.टी. लेपचा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया।

श्री डी.आर थापा ने अपनी नियुक्ति के बाद कहा, "मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और सभी नेताओं का इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे यह जिम्मेदारी दी है। सिक्किम बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए मेरी प्राथमिकता मेरे सिक्किम के लोगों और प्रदेश का विकास होगी।" ■

## कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक नियुक्तियां

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया, पार्टी ने चार फरवरी, 2023 को एक वक्तव्य जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। इस वक्तव्य के अनुसार भाजपा, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष श्री के. अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। ■

# झारखंड में कमल खिलाइए: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 4 फरवरी, 2023 को जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र, देवघर (झारखंड) में आयोजित विशाल विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया और झारखंड में पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजनवाली सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास, भाजपा प्रभारी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश, केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा सांसद श्री निशिकांत दुबे और भाजपा सांसद श्री सुनील सोरेन भी उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि आज देवघर में नैनो तरल यूरिया की फैक्ट्री में काम शुरू हुआ है। विश्व में सबसे पहला तरल नैनो यूरिया इफ्को ने बनाया है। यह संयंत्र 6 करोड़ बॉटल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इससे 6 करोड़ यूरिया बैग की खपत कम होगी। इससे भूमि संरक्षण भी होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। साथ ही, प्रकृति का भी संरक्षण और संवर्धन होगा। इससे पूरे संथाल परगना का विकास होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। इस बार जब देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनने का अवसर आया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी आदरणीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस पद पर प्रतिष्ठित किया।

झारखंड की गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि आज झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग झारखंड राज्य इसलिए बनाया था, ताकि यहां का विकास हो। आदिवासी भाइयों, दलित भाई और पिछड़े वर्ग के भाइयों का कल्याण हो। जब हमारी डबल इंजनवाली सरकार आई तो रघुवर दासजी ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फिर से हेमंत सोरेनजी आ गए। उनके साथ कांग्रेस और राजद वाली भ्रष्टाचारी ताकतें भी जुड़ गईं। श्री शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए, कमल खिलाइए और झारखंड में विकास की डबल इंजनवाली सरकार का पुनः गठन कीजिये। ■

# विकास के प्रति समर्पित डबल इंजनवाली भाजपा सरकार बनाने का आह्वान

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 6 फरवरी, 2023 को त्रिपुरा में सांतिरबाजार और खोवाई में दो विशाल विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया और राज्य की जनता से एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा के विकास के प्रति समर्पित डबल इंजनवाली भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, नॉर्थ-ईस्ट के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ. संबित पात्रा एवं त्रिपुरा चुनाव 2023 के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह सहित क्षेत्र के सभी भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। खोवाई में आयोजित रैली में त्रिपुरा के भाजपा प्रभारी डॉ. महेश शर्मा, सह-प्रभारी श्री समीर उरांव सहित क्षेत्र के सभी भाजपा प्रत्याशी उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन वाली त्रिपुरा सरकार ने राज्य में विकास को एक नया आयाम दिया। आजादी के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा में 50 सालों तक शासन किया, लेकिन त्रिपुरा की जनता आजादी के 70 साल बाद भी घर, बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती रही। हमारी डबल इंजन वाली सरकार ने राज्य के 4 लाख घरों में पीने का पानी दिया जबकि कम्युनिस्ट सरकार ने 27 साल के अपने शासन में केवल 24 हजार घरों में ही पानी पहुंचाया। ये परिवर्तन है। ये फर्क है भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के बीच में।

विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और मोथा वाले, तीनों मिले हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है मोथा के नेताओं को? जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने आदिवासियों पर अत्याचार किया, उस कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने के लिए मोथा ने अलग से मोर्चा खोला है। उन्होंने जनता को उनके वोट के लिए आगाह करते हुए कहा कि आपने कांग्रेस को वोट दिया या मोथा को, तो वोट कम्युनिस्ट के ही पक्ष में जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर से विकास के प्रति समर्पित भाजपा की सरकार बने तो आपको केवल और केवल कमल के निशान पर ही बटन दबाना है। ■

# 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी 6.0 से 6.8 प्रतिशत

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2023 को संसद में 'आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23' पेश किया, जिसका अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5 प्रतिशत रहेगी। इस अनुमान की बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी और घरेलू तौर पर आरबीआई द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना की जा सकती है। सर्वेक्षण कहता है कि वित्त वर्ष 2024 में विकास की गति तेज रहेगी, क्योंकि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के लेखा विवरण पत्रों के मजबूत होने से ऋण अदायगी और पूंजीगत निवेश के शुरू होने का अनुमान है। आर्थिक विकास को लोक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार तथा ऐतिहासिक उपायों जैसे पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से समर्थन मिलेगा, जो निर्माण उत्पादन को बढ़ावा देंगे। आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें निम्न हैं:

## आर्थिक हालात 2022-23 : पूर्ण रिकवरी हो गई है

- महामारी की वजह से दर्ज की गई गिरावट, रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल असर और महंगाई से उबरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अब समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय बेहतरी देखने को मिल रही है, जिससे यह वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व विकास पथ पर अग्रसर हो रही है।
- भारत में जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में भी दमदार रहने की आशा। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय और अब कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट की अगुवाई में निजी पूंजीगत व्यय चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफी मददगार साबित हो रहा है।
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुल ऋणों में वृद्धि जनवरी-नवम्बर 2022 के दौरान औसतन 30.6 प्रतिशत से भी अधिक रही।
- खुदरा महंगाई नवम्बर, 2022 में घटकर फिर से आरबीआई के लक्षित दायरे में आ गई है।

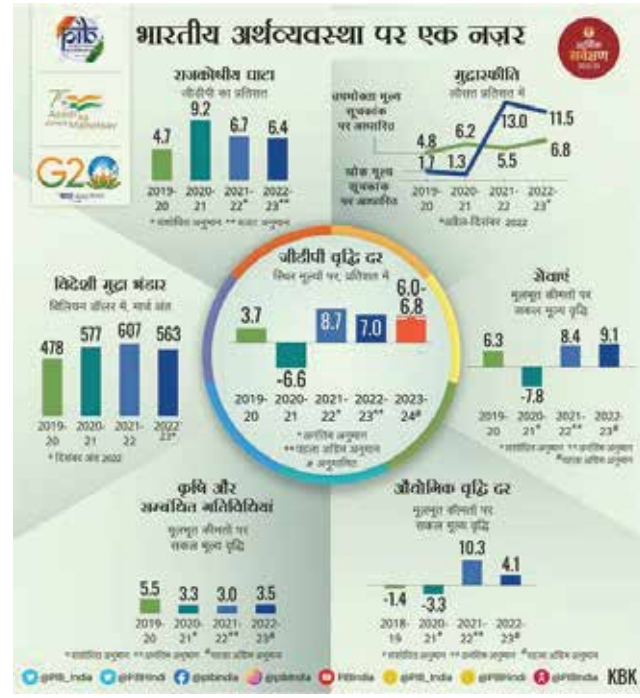


## राजस्व में तेज उछाल

- केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति वित्त वर्ष 2023 के दौरान काफी सुदृढ़ हो गई है, जो कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ने, प्रत्यक्ष करों एवं जीएसटी से होने वाले राजस्व में तेज उछाल और बजट में यथार्थवादी अनुमान लगाए जाने से ही संभव हो पाई है।
- अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दमदार वृद्धि से संभव हुई है।
- जीएसटी अब केन्द्र और राज्य सरकारों का एक अहम राजस्व स्रोत बन गया है। अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में वार्षिक आधार पर 24.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफी अधिक रहने के बावजूद केन्द्र सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर निरंतर विशेष जोर दिया जाता रहा है। केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.7 प्रतिशत के दीर्घकालिक वार्षिक औसत (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2020 तक) से निरंतर बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हो गया है।

## कीमतें एवं महंगाई : सफलतापूर्वक संतुलन स्थापित करना

- जहां एक ओर तीन से चार दशकों के लंबे अंतराल के बाद विकसित

देशों में आसमान छूती महंगाई की वापसी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर भारत में मूल्यवृद्धि एक सीमा में बनी रही।

- वैसे तो भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल, 2022 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई जो कि आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक थी, लेकिन भारत में लक्षित सीमा से बढ़ी हुई महंगाई इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही।
- पेट्रोल और डीजल पर निर्यात शुल्क में कई चरणों में कटौती की गई।
- प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया, जबकि लौह अयस्क एवं सांद्र के निर्यात पर देय कर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
- कपास के आयात पर देय सीमा शुल्क को 14 अप्रैल, 2022 से लेकर 30 सितम्बर, 2022 तक माफ कर दिया गया।
- एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया।

## सामाजिक अवसंरचना और रोजगार : विशेष जोर

- सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली।
- स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 (बीई) में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022 (आरई) में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 1.6 प्रतिशत ही था।
- सामाजिक क्षेत्र पर व्यय वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 (बीई) में 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- आर्थिक समीक्षा में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें कहा गया है कि भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 और वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम विशेषकर सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है।
- असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया जिसका सत्यापन 'आधार' से होता है। 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
- जैम (जन-धन, आधार, एवं मोबाइल) के साथ-साथ डीबीटी ने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ दिया है, जिससे लोगों को सशक्त करते हुए पारदर्शी एवं उत्तरदायी गवर्नेंस के मार्ग में क्रांति आ गई है।
- 'आधार' ने को-विन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और टीके की 2 अरब से भी अधिक खुराक लोगों को पारदर्शी ढंग से देने में अहम भूमिका निभाई है।
- शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में श्रम बाजार मुश्किलों से उबर कर कोविड पूर्व स्तर से ऊपर चला गया है। यही नहीं, बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 के 5.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 4.2 प्रतिशत रह गई है।
- वित्त वर्ष 2022 में स्कूलों में सकल दाखिला अनुपात (जीईआर) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और इसके साथ ही बालक-बालिका अनुपात भी बेहतर हो गया। 6 से 10 साल के आयु वर्ग में आबादी के प्रतिशत के रूप में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में प्राथमिक दाखिले को लेकर जीईआर वित्त वर्ष 2022 में बालिकाओं के साथ-साथ बालकों के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की वजह से कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति की जेब से होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2014 के 64.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2019 में 48.2 प्रतिशत रह गया।
- बाल मृत्यु दर (आईएमआर), 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और नवजात शिशु मृत्यु दर (एनएमआर) में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है।
- 6 जनवरी, 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई हैं।
- 4 जनवरी, 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों को चालू किया गया है।

## जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण : भावी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना

- भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 'नेट जीरो' का संकल्प व्यक्त किया।
- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया।
- गैर-जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 जीडब्ल्यू से भी अधिक हो जाएगी, जिससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29 प्रतिशत की कमी आ जाएगी।
- भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत कम कर देगा।
- वर्ष 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल होगी।
- पर्यावरण के लिए जीवन शैली 'लाइफ' के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबी) नवम्बर, 2022 में जारी किया गया।
- आरबीआई ने 4000 करोड़ रुपये के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबी) की दो किस्तों की नीलामी की।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
- वर्ष 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी और 6 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 जीडब्ल्यू की वृद्धि की जाएगी और जीएचजी के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी की जाएगी।
- आर्थिक समीक्षा में सीसी पर एनएपी के तहत आठ मिशनों की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, ताकि जलवायु से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता, जो कि राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक अहम पैमाना है, अक्टूबर 2022 में 61.6 जीडब्ल्यू दर्ज की गई।
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक पसंदीदा देश बनता जा रहा है; सात वर्षों में कुल निवेश 78.1 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
- सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 62.8 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6.2 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (अगस्त, 2022) किया गया।

## कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

- कृषि और संबंधित क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से मजबूत रहा है। काफी हद तक इसका कारण फसल एवं मवेशी उत्पादकता में वृद्धि, समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को निश्चित आमदनी सुनिश्चित करने, फसलों में विविधता को बढ़ावा देने किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के माध्यम से बाजार अवसंरचना में सुधार लाने तथा कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से ढांचागत सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए गए उपाय रहे हैं।
- वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3 प्रतिशत बढ़ा।
- वर्ष 2018 से अनिवार्य सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का 1.5 गुणा निर्धारित किया गया।
- वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण लगातार बढ़कर 18.6 लाख करोड़ हो गया।
- भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 315.7 मिलियन टन हो गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न।
- योजना के अंतर्गत अप्रैल-जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया।
- कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपये मंजूर।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू।

- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

## उद्योग: निरंतर सुधार

- औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन (जीवीडब्ल्यू) में 3.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए), जो पिछले दशक के पूर्वार्द्ध के दौरान हासिल की गई 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है।
- वर्ष की पहली छमाही के दौरान निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में मजबूत वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन, संवर्द्धित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और मजबूत बैंक एवं कॉरपोरेट बैलेंस शीट के कारण निवेश की मांग में वृद्धि।
- बढ़ी हुई मांग के प्रति उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है।
- जुलाई, 2021 से 18 महीनों के लिए पीएमआई विनिर्माण विस्तार क्षेत्र में कायम रहा है। औद्योगिक विस्तार सूचकांक में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है।
- सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को ऋण में जनवरी, 2022 से औसतन लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बड़े उद्योगों में अक्टूबर, 2022 से दहाई के आंकड़े में वृद्धि देखी गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है।
- भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। यहां हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ तक पहुंच गया।
- फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चार गुणा वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर यह वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया।
- भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए पीएलआई योजनाएं अगले पांच वर्षों में अनुमानित चार लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई हैं। वित्त वर्ष 2022 में पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ का निवेश देखा गया, जो कि वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 106 प्रतिशत था। पीएलआई योजनाओं के कारण 3.85 लाख करोड़ रुपए मूल्य की उत्पादन/बिक्री और 3.0 लाख का रोजगार का सृजन हुआ है।
- जनवरी, 2023 तक 39,000 से अधिक अनुपालनों में कमी आई है और 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है।

## सेवाएं- सुदृढ़ता का स्रोत

- वित्त वर्ष 2022 में 8.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- जुलाई, 2022 से पीएमआई सेवाओं, जो कि सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का संकेतक है, में जबरदस्त विस्तार देखा गया।
- भारत 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यात करने वाले देशों में शामिल था, विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2015 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4 प्रतिशत हो गई।
- कोविड-19 महामारी के दौरान और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की उच्च मांग द्वारा प्रेरित भारत का सेवा निर्यात सशक्त बना रहा।
- जुलाई, 2022 से सेवा क्षेत्र के लिए ऋण में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह।
- वित्त वर्ष 2023 में संपर्क-गहन सेवाएं महामारी से पहले के स्तर की वृद्धि दर को पुनः हासिल करने के लिए तैयार हैं।
- रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि 2021 और 2022 के बीच 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, आवास की बिक्री को महामारी के पूर्व-स्तर पर ले जा रही है।
- होटल ऑक्यूपेंसी दर अप्रैल, 2021 में 30-32 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर, 2022 में 68-70 प्रतिशत हो गई है।
- वित्त वर्ष 2023 में भारत में विदेश पर्यटकों के आगमन के साथ-साथ निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली और कोविड-19 नियमों में ढील के साथ पर्यटन क्षेत्र के पुनर्जीवित होने के संकेत

मिल रहे हैं।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं।
- भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है।

## बाहरी क्षेत्र

- अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा।
- भारत ने अपने बाजार को विभिन्न वर्गों में विविधिकृत किया और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब के लिए अपने निर्यात में बढ़ोतरी की।
- बाजार के विस्तार और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2022 में यूएई के साथ सीईपीए और ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए लागू हुआ।
- भारत 2022 में 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। सेवा निर्यात के बाद प्रेषण बाह्य वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है।
- दिसम्बर, 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन डॉलर पर रहा।
- नवम्बर, 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है।

## विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र

- 30 सितम्बर, 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता 40 जीडब्ल्यू है।
- वित्त वर्ष 2022 के दौरान 17.2 लाख जीडब्ल्यूएच विद्युत का उत्पादन हुआ।
- कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता (उद्योग, जिनकी मांग एक मेगावाट (एमडब्ल्यू) और अधिक है), 31 मार्च, 2021 के 460.7 जीडब्ल्यू के मुकाबले 31 मार्च, 2022 को 482.2 जीडब्ल्यू हो गयी।

## भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना

- राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के निर्माण में तेजी; वित्त वर्ष 2016 के 6061 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों का निर्माण किया गया।
- वित्त वर्ष 2020 के 1.4 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बजट परिव्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2.4 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई।
- अक्टूबर, 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन सब्जियों/फलों का परिवहन किया।
- आठ वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता दोगुनी हुई।

## भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117.8 करोड़ (सितम्बर, 2022 तक) है, 44.3 प्रतिशत उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में।
- कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 98 प्रतिशत मोबाइल फोन द्वारा जुड़े हुए हैं।
- मार्च, 2022 में भारत का कुल टेली–घनत्व 84.8 प्रतिशत है।
- 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रसार भारती (भारत का स्वायत्त लोक प्रसारक) 479 स्टेशनों के माध्यम से 23 भाषाओं और 179 उप-भाषाओं में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिसकी पहुंच 92 प्रतिशत क्षेत्र और कुल आबादी के 99.1 प्रतिशत तक है।

## आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का सारांश

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5 प्रतिशत रहेगी
- अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7 प्रतिशत (वास्तविक) रहने का अनुमान है, पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7 प्रतिशत रही थी
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी-नवम्बर, 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5 प्रतिशत रही
- केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), जो वित्त वर्ष 2023 के आठ महीनों के दौरान 63.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण रहा है
- निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया, जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है, में महत्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है
- वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई, वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई है
- वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4 प्रतिशत रही, जो 2013-14 के बाद के सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल और परिवहन की मजबूती से समर्थन मिला ■

# हमें 2047 तक ऐसा भारत बनाना है जिसमें अतीत का गौरव और आधुनिकता के स्वर्णिम अध्याय हों: राष्ट्रपति

**आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदला है**

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को कहा कि देश में अमृतकाल का 25 वर्ष का कालखंड, स्वतन्त्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है और हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो।

राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके अमृतकाल में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए शत-प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है।

**राष्ट्रपति ने कहा,**

- हमें ऐसा भारत बनाना है, जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भी समर्थ हो।
- ऐसा भारत— जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो।
- ऐसा भारत— जिसकी युवाशक्ति और नारीशक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हों।
- ऐसा भारत— जिसकी विविधता और अधिक उज्ज्वल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो।

## देश में आया सकारात्मक परिवर्तन

देश में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार के लगभग नौ वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदला है।

उन्होंने कहा कि जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतज़ार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली हैं।

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वह इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे विकसित देश भी प्रेरणा ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि यही वो नींव है, जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करती है।

## भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबों को स्थाई समाधान और उनके स्थाई सशक्तीकरण के लिए काम करने वाली

सरकार है।

उन्होंने कहा कि आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनकल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हर बाधा को दूर करने वाली सरकार है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है।

## देशहित सदैव सर्वोपरि

अपने संबोधन में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने देशहित को सदैव सर्वोपरि रखा, नीति-रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छाशक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LoC से लेकर LAC तक हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर तीन तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' तक एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थाई और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है।

उन्होंने कहा कि अब तक पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसी योजनाओं और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है।

## 'गरीबी हटाओ' अब केवल नारा नहीं

राष्ट्रपति ने कहा कि 'गरीबी हटाओ' अब केवल नारा नहीं रह गया है। अब मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थाई समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, जैसे— गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है।

उन्होंने कहा कि गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी 'आयुष्मान भारत योजना' शुरु की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है, उनके 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। आज देशभर में करीब नौ हजार जनऔषधि केन्द्रों में बहुत कम कीमत में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20 हजार करोड़ रुपए बचे हैं।

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है, जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है।

उन्होंने कहा कि रेहड़ी-ठेले-फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी, अपना व्यापार-कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है। इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक करीब 40 लाख साथियों को इसके तहत ऋण दिया जा चुका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है।

## कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं

महिलाओं के सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तीकरण रहा है।

उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है, वह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार के आने के बाद भारत में गरीबों के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11 हजार घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन ढाई लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े।

उन्होंने कहा कि हर रोज 55 हजार से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया। बीते आठ-नौ वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन में दो कॉलेजों की स्थापना हुई है, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। सिर्फ दो साल के भीतर भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी दी है। ■

# 'आज पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता और आशा है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब लोकसभा में दिया। श्री मोदी ने कहा कि माननीया राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को अपने दूरदर्शी संबोधन में राष्ट्र को सटीक दिशा दी है। उन्होंने कहा कि माननीया राष्ट्रपति के संबोधन ने भारत की 'नारी शक्ति' को प्रेरित किया है और भारत के जनजातीय समुदायों में गर्व की भावना उत्पन्न करते हुए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र के 'संकल्प से सिद्धि' का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तरह-तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दृढ़ संकल्प से देश हमारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि सदी में एक बार आने वाली आपदा और युद्ध के दौरान देश को सटीक ढंग से संभालने से हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है। व्यापक उथल-पुथल के इस दौर में भी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।



**यूपीए के कार्यकाल में भारत का 'खोया हुआ दशक' कहा जाता था, जबकि आज लोग वर्तमान दशक को 'भारत का दशक' कह रहे हैं**

श्री मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता और आशा है। प्रधानमंत्री ने इस सकारात्मकता का श्रेय स्थिरता, भारत की वैश्विक साख, भारत की बढ़ती क्षमता और भारत में उभरती नई संभावनाओं को दिया। श्री मोदी ने देश में भरोसे के माहौल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में स्थिर और निर्णायक सरकार है। उन्होंने इस विश्वास को रेखांकित किया कि आज सुधार मजबूरी से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से लागू किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है।

श्री मोदी ने 2014 से पहले के दशक की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि 2004 से 2014 के बीच के साल घोटालों से भरे रहे और साथ ही देश के कोने-कोने में आतंकी हमले हो रहे थे। इस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज बहुत ही कमजोर हो गई। वह युग 'मौके में मुसीबत' वाला था।

## आज आत्मविश्वास से भरा है देश

इस बात पर बल देते हुए कि देश आज आत्मविश्वास से भरा है और अपने सपनों एवं संकल्पों को साकार कर रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है और इसका श्रेय भारत की स्थिरता व संभावनाओं को देती है। उन्होंने कहा कि यूपीए के तहत भारत को 'खोया हुआ दशक' कहा जाता था, जबकि आज लोग वर्तमान दशक को 'भारत का दशक' कह रहे हैं।

भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए रचनात्मक आलोचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आलोचना एक 'शुद्धि यज्ञ' की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि रचनात्मक आलोचना के बजाय कुछ लोग बाध्यतावश आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान हमने ऐसे आलोचक देखे हैं, जो रचनात्मक आलोचना के बजाय निराधार आरोप लगाते हैं।

## 140 करोड़ भारतवासियों का आशीर्वाद मेरा 'सुरक्षा कवच'

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की आलोचना उन लोगों को सही नहीं मालूम होगी जो पहली बार बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक राजवंश के बजाय 140 करोड़ भारतीयों के परिवार के सदस्य हैं। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों का आशीर्वाद मेरा 'सुरक्षा कवच' है।

प्रधानमंत्री ने वंचित और उपेक्षित लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जोर देकर कहा कि सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को मिला है। भारत की नारी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने बताया कि भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कोई

कसर नहीं छोड़ी गई है।

उन्होंने कहा कि जब भारत की माताएं सशक्त होती हैं, तो लोग सशक्त होते हैं और जब लोग सशक्त होते हैं तो यह समाज को सशक्त बनाता है जिससे देश सशक्त होता है। श्री मोदी ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि सरकार ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया है और उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें सम्मानित किया है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत के आम नागरिक सकारात्मकता से भरे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय समाज में नकारात्मकता से निपटने की क्षमता है, लेकिन वह इस नकारात्मकता को कभी स्वीकार नहीं करता है।

### मुख्य बातें

- राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को अपने दूरदर्शी संबोधन में देश को सटीक दिशा दी है
- आज सुधार मजबूरी से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से लागू किए जाते हैं
- यूपीए के कार्यकाल में भारत का 'खोया हुआ दशक' कहा जाता था, जबकि आज लोग वर्तमान दशक को 'भारत का दशक' कह रहे हैं
- भारत लोकतंत्र की जननी है, मजबूत लोकतंत्र के लिए रचनात्मक आलोचना जरूरी है और आलोचना 'शुद्धि यज्ञ' की तरह है
- रचनात्मक आलोचना के बजाय कुछ लोग बाध्यकारी आलोचना में लिप्त हैं
- 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद ही मेरा 'सुरक्षा कवच' है
- हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया है। हमने उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें सम्मानित किया है
- भारतीय समाज में नकारात्मकता से निपटने की क्षमता है, लेकिन वह इस नकारात्मकता को कभी भी स्वीकार नहीं करता है ■

## 'वंदे भारत ट्रेनें भारत की गति और पैमाने का प्रतिबिंब हैं'



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दो ट्रेनें हैं— मुंबई-सोलापुर वंदे भारत और मुंबई-साईंनगर शिरडी वंदे भारत। उन्होंने मुंबई में सड़क यातायात की भीड़ को कम करने और वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए दो सड़क परियोजनाओं— सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत में रेलवे, विशेष रूप से महाराष्ट्र में उन्नत रेल-संपर्क के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पहली बार दो वंदे भारत ट्रेनों को एक ही दिन हरी झंडी दिखाई गई है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे आर्थिक केंद्रों को आस्था के केंद्रों से जोड़ेंगी, जिससे कॉलेज, कार्यालय, व्यवसाय, तीर्थ यात्रा और कृषि उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वालों को लाभ होगा।

श्री मोदी ने कहा कि नई वंदे भारत ट्रेनों से शिरडी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटन के साथ-साथ तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस से पंढरपुर, सोलापुर, अक्कलकोट और तुलजापुर की तीर्थ यात्रा और भी अधिक आसान हो जायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत की भव्य तस्वीर है। ये भारत की गति और पैमाने का प्रतिबिंब है। वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने की गति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक देश के 17 राज्यों के 108 जिलों को जोड़ने वाली 10 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज शुरू की जा रही विभिन्न परियोजनाएं जीवन को और आसान बनाएंगी। उन्होंने कहा कि ऊपरी सड़कें (एलिवेटेड रोड) पूर्वी और पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्रों तथा अंडरपास को जोड़ेंगी, जो महत्वपूर्ण हैं।

श्री मोदी ने 21वीं सदी के भारत के लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की जरूरत को दोहराया, क्योंकि इससे नागरिकों का जीवन-यापन व्यापक रूप से आसान होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत, मेट्रो के विस्तार और नए हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों के निर्माण के पीछे यही सोच है। बजट भी इस सोच को मजबूत करता है, क्योंकि पहली बार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष रूप से 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें रेलवे की हिस्सेदारी 2.5 लाख करोड़ रुपये है। ■

# अमृतकाल में सहकारिता की अहम भूमिका

अमित शाह

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए 'अमृतकाल' के प्रथम बजट ने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्प को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ाने, करों में कमी लाने और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार किया गया यह विकासोन्मुखी बजट न केवल भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि वैश्विक निराशा के वातावरण को भी बदलने में सहायक होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में बढ़ई, सुनार, कुम्हार और अन्य कामगारों की मेहनत के महत्व को समझते हुए उनके हित में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कई योजनाएं लाई गई हैं। समाज में इन वर्गों के महत्वपूर्ण योगदान को एक लंबे समय से समुचित सम्मान और मान्यता की दरकार थी, जिसे इस बजट में पूरी प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंत्रालय का प्रभार दिया गया। इस बजट ने अनेक अनुकूल उपायों की घोषणा करके सहकारी क्षेत्र को एक आवश्यक बूस्टर खुराक प्रदान करने का काम किया है। बजट में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना की घोषणा की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण सुविधा होगी। यह सहकारिता की दिशा और दशा बदलने वाला निर्णय है। नई सहकारी निर्माण समितियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में 31 मार्च, 2024 से पहले कार्यरत समितियों पर 15 प्रतिशत की रियायती आयकर दर की घोषणा की गई है।

चीनी सहकारी मिलों को बहुप्रतीक्षित राहत देने का काम भी इस बजट में हुआ है। निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के दावों को अब 'व्यय' माना जाएगा। इससे चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सहकारी समितियां लंबे समय से हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधताओं के कारण इनके लाभ पूरे देश को समानता से नहीं मिल पा रहे है। तेजी से बढ़ रहे सहकारी क्षेत्र को कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एक 'राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय' स्थापित करने का भी काम हो रहा है। हाल में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता ज्ञापन प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कामन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में समर्थ करेगा। जल्द ही प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को एफपीओ का दर्जा देने की पहल की जाएगी।

**चीनी सहकारी मिलों को बहुप्रतीक्षित राहत देने का काम भी इस बजट में हुआ है। निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के दावों को अब 'व्यय' माना जाएगा। इससे चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है**

सरकार ने सहकारी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कई नए कदमों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत निर्यात, बीज और आर्गेनिक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सहकारी समितियां छोटे स्तर के उद्यमियों को उत्पादन लागत कम करने के लिए रियायती दरों पर कच्चे माल की खरीद में भी मदद करती हैं। साथ ही, वे उत्पादकों को बिक्री मूल्य में कटौती करने और उच्च बिक्री व लाभ सुनिश्चित करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से बिचौलियों को हटाकर उनके उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मंच भी प्रदान करती हैं।

शहर-गांव के विभाजन को पाटने और आय सृजन के अवसर पैदा करने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। वे बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान उपलब्ध कराने के कारण अर्थव्यवस्था की चालक भी हैं और भारत के बढ़ते निर्यात बाजारों में अहम योगदानकर्ता भी। सहकारी समितियों की सफलता की तमाम कहानियां हैं। डेयरी सहकारी समितियों ने देश में दुग्ध क्रांति

# भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंजानिया की सत्तारूढ़ पार्टी के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

तंजानिया की सत्तारूढ़ पार्टी चामा चा मापिन्दुज़ी (सीसीएम) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25 से 31 जनवरी, 2023 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल को 'भाजपा को जानो' पहल के अंतर्गत आमंत्रित किया गया था, जिसे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर आरंभ किया गया था।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीसीएम के उपाध्यक्ष श्री अब्दुलरहमान उमर किनाना ने किया और इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में श्री अब्दुल्ला मविनी, सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य श्री थदेओ बर्टन म्बोमा, आईटी प्रमुख श्री मसाफिरी विल्बर्ट मारवा, वाइस चेयरपर्सन के निजी सचिव श्री सलुम बकरी सुमा और वाइस चेयरपर्सन के निजी सहायक शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों दलों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और प्रतिनिधिमंडल को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली से परिचित कराना था।

इस प्रतिनिधिमंडल ने 31 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं तक पार्टी के संदेश और कार्यक्रमों को पहुंचाने के विभिन्न पहलुओं और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के तंत्र के बारे में बताया। उन्होंने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क सहित दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पांडा और भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी श्री विजय चौथाईवाले से बातचीत की।

यात्रा के अंत में श्री किनाना ने कहा, "हमने विचारधारा, संगठन और जनता के साथ संवाद के मामले में भाजपा से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा जन-केंद्रित पार्टी बनी हुई है, जो भारतीय लोगों और विशेष रूप से गरीब लोगों के जीवन की चिंता करती है।" ■

की शुरुआत की, जिससे निकला अमूल आज प्रचलित नाम बन गया है। इसी तर्ज पर कुछ महिलाओं द्वारा शुरू किया गया लिज्जत पापड़ हर घर में पहुंच रहा है। इफ्को और कृभको आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं ने देश में कृषि क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर कई सहकारी समितियां, जैसे शहरी सहकारी बैंक, पैक्स, आवास और मत्स्य पालन सहित अन्य अनेक सहकारी समितियां, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।

आज देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्माता, उपभोक्ता, वित्तीय पोषण या किसी न किसी अन्य रूप में सहकारिता से जुड़ी हुई है, जिसमें सहकारी समितियां पैक्स के माध्यम से देश के 70 प्रतिशत किसानों को कवर करती हैं। देश में 33 राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, 363 जिला स्तरीय सहकारी बैंक और 63,000 पैक्स हैं। इसके अलावा, देश के 19 प्रतिशत कृषि वित्त का प्रबंध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही, 35 प्रतिशत उर्वरक वितरण, 30 प्रतिशत उर्वरक उत्पादन, 40 प्रतिशत चीनी उत्पादन, 13 प्रतिशत गेहूं की खरीद और 20 प्रतिशत धान की खरीद केवल सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। लगभग 500 सहकारी समितियों को जेएम पोर्टल में भी पंजीकृत किया गया है, जिससे वे 40 लाख से अधिक विक्रेताओं से खरीदारी कर सकें। जिस तरह मोदी जी ने 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के साथ हाल तक उपेक्षित रहीं सहकारी समितियों को देश के आर्थिक परिदृश्य में आगे लाने का काम किया है, उससे वे जल्द ही भारत के विकास इंजन की एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी कड़ी साबित होंगी। ■

*(लेखक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं)*

# 'परीक्षा में नकल करना आपको जीवन में कभी सफल नहीं बनाएगा'

**'परीक्षा पे चर्चा' के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। बातचीत से पहले प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित छात्रों के प्रदर्शन को भी देखा। परीक्षा पे चर्चा की परिकल्पना प्रधानमंत्री द्वारा की गई है जिसमें छात्र, अभिभावक और शिक्षक उनके साथ जीवन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के आयोजन में इस वर्ष 155 देशों से लगभग 38.80 लाख पंजीकरण हुए**

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहली बार है कि 'परीक्षा पे चर्चा' गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि अन्य राज्यों से नई दिल्ली आने वालों को भी गणतंत्र दिवस की झलक मिली। उन्होंने अपने लिए परीक्षा पे चर्चा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन लाखों सवालों की ओर इशारा किया जो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सामने आए। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। कोटि-कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा लेते हैं और इससे मुझे खुशी मिलती है। यह देखना मेरा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है।

## निराशा से निपटना

खराब अंक के मामले में पारिवारिक निराशा के बारे में एक प्रश्न का समाधान बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार के लोगों को बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेट्स के कारण कर रहे हैं तो वह चिंता का विषय है।

श्री मोदी ने हर सफलता के साथ प्रदर्शन के बढ़ते मानकों और बढ़ती अपेक्षाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि आसपास की उम्मीदों के जाल में फंसना अच्छा नहीं है और व्यक्ति को अपने भीतर देखना चाहिए तथा उम्मीद को अपनी क्षमताओं, जरूरतों, इरादों और प्राथमिकताओं से जोड़ना चाहिए।

## परीक्षा की तैयारी और समय-प्रबंधन

परीक्षा की तैयारी कहां से शुरू करें और तनावपूर्ण स्थिति के कारण भूलने की स्थिति और परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन के बारे में प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री मोदी ने परीक्षा के साथ या उसके बिना सामान्य जीवन में समय प्रबंधन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम कभी नहीं थकता, बल्कि काम नहीं करना इंसान को थका देता है।

## परीक्षा में अनुचित साधन और शार्टकट

प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि छात्रों ने परीक्षा के दौरान कदाचार से निपटने के तरीके खोजने का विषय उठाया और नैतिकता में आए नकारात्मक बदलाव की ओर इशारा किया, जहां एक छात्र परीक्षा में नकल करते समय पर्यवेक्षक को मूर्ख बनाने में गर्व महसूस करता है। श्री मोदी ने कहा कि यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है।

उन्होंने छात्रों से यह भी कहा कि वे तरीके खोजने और नकल सामग्री तैयार करने में समय बर्बाद करने से बचें और उस समय को सीखने में व्यतीत करें। श्री मोदी ने कहा कि दूसरी बात, इस बदलते समय में, जब हमारे आसपास का जीवन बदल रहा है, आपको कदम-कदम पर परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा

कि ऐसे लोग केवल कुछ परीक्षाओं को ही पास कर पाते हैं, लेकिन अंततः जीवन में असफल हो जाते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा में नकल करने से जीवन सफल नहीं हो सकता। आप एक या दो परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन यह जीवन में संदिग्ध बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। परीक्षा तो आती है, जाती है, लेकिन हमें जिंदगी जी भर के जीनी है। इसलिए हमें शॉर्टकट की ओर नहीं जाना चाहिए।

## आलोचना से निपटना

नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों तथा मीडिया के आलोचनात्मक दृष्टिकोण से निपटने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वे इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना एक समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व-शर्त है।

उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कौन आपके काम की आलोचना कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजकल माता-पिता रचनात्मक आलोचना के बजाय अपने बच्चों की क्षमता में बाधा डालने वाले बन गए हैं और उनसे इस आदत को छोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि बच्चों का जीवन प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं बदलेगा।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग आरोप लगाते हैं, आलोचना नहीं करते। श्री मोदी ने कहा कि आरोपों और आलोचनाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि आलोचना को आरोप समझने की गलती न करें।

## गेमिंग और ऑनलाइन लत

ऑनलाइन गेम व सोशल मीडिया की लत और परिणाम में असर डालने के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला निर्णय यह तय करना है कि आप स्मार्ट हैं या आपका गैजेट स्मार्ट है। समस्या तब शुरू होती है जब आप गैजेट को अपने से ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं। किसी की स्मार्टनेस स्मार्ट गैजेट को स्मार्ट तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाती है और उन्हें उत्पादकता में मदद करने वाले उपकरणों के रूप में व्यवहार करती है।

श्री मोदी ने कहा कि स्क्रीन पर औसत समय का बढ़ना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक अध्ययन के अनुसार, एक भारतीय के लिए स्क्रीन पर होने का औसत समय छह घंटे तक है। ऐसे में गैजेट हमें गुलाम बना लेता है।

श्री मोदी ने कहा कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और हमें हमेशा अपने गैजेट्स का गुलाम बनने के बारे में सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक से परहेज नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को जरूरत के हिसाब से उपयोगी चीजों तक सीमित रखना चाहिए।

## परीक्षा के बाद तनाव

कड़ी मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने और तनाव परिणामों को कैसे प्रभावित करता है, के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा के बाद तनाव का मुख्य कारण इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना है कि परीक्षा अच्छी हुई या नहीं। उन्होंने छात्रों के बीच तनाव पैदा करने वाले कारक के रूप में प्रतिस्पर्धा पर भी प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि छात्रों को अपनी आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करते हुए स्वयं और अपने परिवेश से जीना व सीखना चाहिए।

जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं है और परिणामों के बारे में अधिक सोचना दैनिक जीवन का विषय नहीं होना चाहिए।

## नई भाषाओं को सीखने के लाभ

प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत के बारे में कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि भारत सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियों का देश है। उन्होंने कहा कि नई भाषा सीखना एक नया संगीत वाद्ययंत्र सीखने के समान है। श्री मोदी ने कहा कि एक क्षेत्रीय भाषा सीखने का प्रयास करके आप न केवल भाषा की अभिव्यक्ति बनने के बारे में सीख रहे हैं, बल्कि क्षेत्र से जुड़े इतिहास और विरासत के द्वार भी खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दैनिक दिनचर्या पर बोझ के बिना एक नई भाषा सीखने पर जोर देना चाहिए।

## छात्रों को प्रेरित करने में शिक्षकों की भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कहा कि शिक्षकों को लचीला होना चाहिए और विषय व पाठ्यक्रम के बारे में बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए। शिक्षकों को हमेशा छात्रों में जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह उनकी बड़ी ताकत है।

श्री मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें अनुशासन स्थापित करने के लिए शारीरिक दंड का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमें संवाद और तालमेल चुनना चाहिए।

## छात्रों का व्यवहार

समाज में छात्रों के व्यवहार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि माता-पिता को समाज में छात्रों के व्यवहार के दायरे को सीमित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को विस्तार देने का अवसर देना चाहिए, उन्हें बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। अपने बच्चों को समाज के विभिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज में छात्र के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। ■

# भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न

भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 29-30 जनवरी, 2023 को बेलगांव (कर्नाटक) में संपन्न हुई।

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री राजकुमार चाहर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कृषि बजट को 27 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख 35 हजार करोड़ करने का काम किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने का कार्य किया। साथ ही साथ किसानों को सशक्त, समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि के स्वास्थ्य को जांचनेवाली सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, ई-नाम मंडिया, कुसुम योजना, किसान रेल, किसान उड़ान ऐसी अनेकानेक किसान कल्याणकारी योजनाएं देने का भागीरथी कार्य किया है।

श्री चाहर ने कहा कि किसान मोर्चा मोटे अनाज को प्रोत्साहित, प्रसारित करने व अधिकाधिक खपत हेतु विभिन्न स्थानों पर सेमिनार व कार्यक्रम आयोजित करेगा। हम प्राकृतिक खेती अभियान के तहत 1,00,000 गांवों तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु नदियों के किनारे पदयात्रा एवं सेमिनार आयोजित करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा आगामी 24 फरवरी को पीएम सम्मान निधि योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर देश के सभी जिलों में पीएम सम्मान निधि योजना के किसान लाभार्थियों से संपर्क एवं संवाद करने हेतु पीएम किसान लाभार्थी संपर्क-संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा।

भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि किसान योगी की भूमिका निभाता है वह अपने तप से सभी को अन्न उपलब्ध कराता है।

भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी.टी. रवि ने चुनावी राज्यों में किसान मोर्चा की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

समापन सत्र में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं को लेकर किसान लाभार्थियों के घर-घर तक संपर्क अभियान चलाएं एवं किसान मोर्चा सरकार व किसानों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएं, ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से किसानों को पूर्णतः लाभ मिल सकें। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लें और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की पहचान उनके क्षेत्र में एक पदाधिकारी की नहीं, बल्कि एक किसान नेता के रूप में उभरकर सामने आनी चाहिए। ■

### एमएलसी चुनाव परिणाम -2023

## भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 4 और महाराष्ट्र में 1 सीट जीती

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव की सभी पांच सीटों पर मतगणना 03 फरवरी, 2023 को हुई। मतगणना के बाद घोषित परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने पांच में से चार सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गयी। वहीं, समाजवादी पार्टी को सभी पांच सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जहां तक भाजपा की बात है तो उसे बरेली-मुरादाबाद ब्लॉक स्नातक सीट, गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर-उन्नाव स्नातक ब्लॉक और झांसी-इलाहाबाद शिक्षक ब्लॉक सीट पर जीत हासिल हुई। कानपुर शिक्षक प्रखंड सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसी तरह महाराष्ट्र में भाजपा को एक सीट पर जीत मिली। कोंकण शिक्षक सीट पर भाजपा उम्मीदवार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे ने महा विकास अघाडी समर्थित उम्मीदवार बलराम पति को हराया, जबकि इन पांच सीटों में से चार सीटों पर एमवीए ने जीत हासिल की। ■

# जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जनवरी को 'मन की बात' की 97वीं कड़ी में पद्म पुरस्कार, मिलेट (मोटे अनाज), भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों समेत कई विषयों पर चर्चा की। अपने रेडियो कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन, शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परम्पराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

2023 की पहली 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदायों से जुड़ी चीज़ों के संरक्षण और उन पर शोध के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुइ, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि धानीराम टोटो, जानुम सिंह सोय और बी. रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्धी, जारवा और ओंगे जैसी आदि-जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे– हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी।

श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान, नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है, जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्द झाडीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार नॉर्थ-ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे रामकुईवांगबे निउमे, बिक्रम बहादुर जमातिया और करमा वांगचु को भी सम्मानित किया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद न हो। हर किसी की संगीत की पसंद अलग-अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं, जो, संतूर, बम्हुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक

वाद्ययंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद ज़ाज़, मोआ सु-पोंग, री-सिंहबोर कुरका-लांग, मुनि-वेंकटप्पा और मंगल कांति राय ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ़ चर्चा हो रही है।

## लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं मिलेट्स

अनाज (मिलेट) पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान के कोने-कोने में G-20 की बैठकें लगातार चल रही हैं और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G-20 की बैठक हो रही है, मिलेट्स से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं।

## पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क में 5वीं

'मन की बात' के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क में 5वीं है। सिर्फ पेटेंट्स की बात करें, तो पिछले पांच वर्षों में इसमें करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और अब वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 80 नंबर के भी पीछे था। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है। ■

# प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता: सर्वे

अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 78 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं।

रेटिंग के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अन्य विश्व नेताओं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। इस रेटिंग में 22 वैश्विक नेताओं का की लोकप्रियता को लेकर सर्वेक्षण किया गया था।

पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ने कहा कि 'ग्लोबल लीडर अप्रूवल' सर्वे

इस साल 26-31 जनवरी तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जिसने प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के सात-दिवसीय मूविंग एवरेज को अलग-अलग सैंपल साइज के साथ तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 78 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की और श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बहुत आगे रहे, जिन्हें 40 प्रतिशत रेटिंग प्राप्त हुई।

मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 68 प्रतिशत रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आए और स्विस राष्ट्रपति एलेन बेर्सेट 62 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ■

## कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

**आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!**

**सदस्यता प्रपत्र**

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

| सदस्यता | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एक वर्ष | ₹350/- | ☐ | आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी) | ₹3000/- | ☐ |
| | तीन वर्ष | ₹1000/- | ☐ | आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी) | ₹5000/- | ☐ |

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

**अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें**

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में 24 जनवरी, 2023 को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023' के विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 27 जनवरी, 2023 को 'परीक्षा पर चर्चा' के 6वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 31 जनवरी, 2023 को संसद के बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 25 जनवरी, 2023 को हैदराबाद हाउस में मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल-सिसी से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 26 जनवरी, 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive



**प्रेषण तिथि:** (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
**डाकघर:** लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23


# नई दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस परेड का भव्य दृश्य

छायाकार: अजय कुमार सिंह